

प्रेषक,

एनोएसोनपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,  
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: १७ जून, २००८

विषय:-

मै० मर्क (MIRC) इलैक्ट्रॉनिक्स लि० UNIT-2 के मैगा प्रोजेक्ट हेतु जनपद हरिद्वार की तहसील रुडकी के ग्राम मुण्डियाकि में कुल 2.9020 हौ० भूमि क्य करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-३१९/भूमि व्यवस्था-भूक्य-८/ दिनांक ०२ मई, २००६ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै० मर्क (MIRC) इलैक्ट्रॉनिक्स लि० UNIT-2 के मैगा प्रोजेक्ट हेतु उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, २००१) (संशोधन) अधिनियम, २००३ दिनांक १५-१-२००४ की धारा-१५४(४)(३)(क)(V) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार की तहसील रुडकी के ग्राम मुण्डियाकी के खसरा सं०-३९९ से ४०१, ४०५ से ४१० तक कुल रकम 2.9020 हौ० भूमि क्य किये जाने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

१- केता धारा-१२९-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्य करने के लिये अहं होगा।

२- केता बैंक या वित्तीय तंत्र से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-१२९ के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

३- केता द्वारा क्य की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्य विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में

.....(2)

अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (वाशिंग मशीन एवं अन्य कन्ज्यूमर ड्यूरेबल उत्पादो के निर्माण) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्य किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्य, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्य से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकरणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6— शासन द्वारा दी गई भूमि क्य की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी एंव भूमि का कब्जा प्राप्त होने के 180 दिन के भीतर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा एंव दो वर्ष के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना होगा।

7— मैगा प्रोजेक्ट के लिये प्रस्तावित ग्राम मुण्ड्याकी, तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार स्थित खसरा सं0-399 से 401, तथा 405 से 410 तक कुल रकबा 2.9020 है। भूमि भारत सरकार वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 50/2003 सेंट्रल एक्साइज दिनांक 10 जून 2003 जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत Category & C Industrial Activity in Non Industrial Area (To Be Notified along with extension) के अधीन कगांक-9 पर अधिसूचित है। जिसे अधिसूचना संख्या 27-27/2005-सी0ई0 दिनांक 19 मई, 2005 के एनैक्जर-2 में Industrial Activity in Non Industrial Area के रूप में प्रतिस्थापित किया जा चुका है, में स्थापित उद्योग के पर्याप्त विस्तार अथवा नये उद्योग की स्थापना पर (नकारात्मक उद्योगों को छोड़कर) भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।

8— GIDCR-2005 में औद्योगिक इकाई के भवन निर्माण के लिये दिये गये मानकों, उपबन्धों, विधियों/उपविधियों का पूर्णतः पालन करना होगा।

9— प्रस्तावित विशेष औद्योगिक आस्थान की आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्य अनुबन्धित है। अतः विशेष औद्योगिक आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व क्यानुबन्धित भूमि के क्य विलेख पत्र (Sale Deed) नियंत्रा: निष्पादित कराकर GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू-उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् विशेष औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली कम्पनी की प्रस्तावित इकाई का भवन मानचित्र सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराना होगा।

10— विशेष औद्योगिक आस्थान के रख-रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। कम्पनी द्वारा आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सम्बन्ध में सभी स्पष्ट सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

11— आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निनिश्चयन विभाग, उत्तरांचल पॉवर कॉर्पोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/ अनुमति/ अनुमोदन/ अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

12— कम्पनी उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटैकिंग लिखित में देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त 70 प्रतिशत नियमित रोजगार/ सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/ भूखण्ड की क्य विलेख पत्र/ लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

13— इकाई द्वारा क्य की जाने वाली भूमि का उपयोग वाशिंग मशीन एवं टिकाउ उत्पादों विनिर्माण उद्योग तथा उसके वांछित आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

14— विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों यथा प्रदेश की औद्योगिक निति के अन्तर्गत एसी औद्योगिक इकाईयाँ, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।

15— मैगा प्रोजेक्ट हेतु स्पॉट जोनिंग के लिये निश्चित मानकों/ दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जायेगा तथा प्रोजेक्ट में प्रस्तावित पूँजी निवेश 31 मार्च, 2010 तक पूर्ण करना होगा।

16— प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सम्बन्धित इकाई का होगा। प्रश्नगत अनापत्ति मात्र भूमि क्य व्यवस्था के सन्दर्भ में दी जा रही है। आवेदक को आवेदित भूमि का नियमानुसार अपने पक्ष में क्य करने के उपरान्त नियमानुसार मैगा प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित/विनियमित कराना होगा।

17— प्रश्नगत इकाई की स्थापना के संबंध में अनापत्ति मात्र भूमि क्य व्यवस्था के संदर्भ में दी जा रही है और पैकेज के अन्तर्गत देय सुविधाओं/छूट हेतु इकाई की अर्हता स्वतः निर्धारित नहीं करती है जो इकाई की स्थापना के पश्चात आवेदन करने पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

18— किसी भी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई गूण पर क्षेत्र न हो इसके लिये भूमि क्य के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

19— भूमि का विक्य अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विक्य किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

20— नियमानुसार योजना प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकताओं/अनापत्तियां प्राप्त कर ली जायेंगी।

21— उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त करदी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन०एस०नपलच्याल)

प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— आयुक्त, गढवाल मण्डल, देहरादून।
- 3— सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4— सचिव, श्रम एंव सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5— मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा एंव प्रबंध निदेशक सिडकुल, देहरादून।

6- श्री राजेश राधकृष्णन, जानरल गैरेजर, ऑपरेशन एण्ड प्रोजेक्ट, गर्क इलैक्ट्रॉनिक्स<sup>1</sup>  
लि0, जी0-1,MIDC, मकाली केव्स रोड, अन्धेरी ईस्ट, मुम्बई ।  
निदेशक, एन0आई0सी10, उत्तराखण्ड, सचिवालय ।  
गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,  
20/11/2017  
(सन्तोष बडोनी)  
अनुसचिव ।